

प्रेषक,

टीकम सिंह पवार
संयुक्त सचिव
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून ।

पेयजल अनुभाग

देहरादून दिनांक 24 अक्टूबर, 2007

विषय:- राज्य सैक्टर की ग्रामीण पेयजल योजनान्तर्गत कालूवाला-भंगलाना पेयजल योजना हेतु वर्ष 2007-08 में प्रशासकीय/वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय पत्र संख्या 2765/धनावंटन प्रस्तावा/दिनांक 30.08.07 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 में राज्य सैक्टर ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद देहरादून की कालूवाला-भंगलाना पेयजल योजना के सिविल कार्यों हेतु उपलब्ध कराये गये रु0 336.01 लाख के प्राक्कलन पर टीएसी वित्त के परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि रु0 293.50 लाख (रु0 दो करोड़ तिरानबे लाख पचास हजार मात्र) के प्राक्कलन पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ ही उक्त अनुमोदित लागत का 40 प्रतिशत अर्थात् रु0 117.40 लाख (रु0 एक करोड़ सत्रह लाख चालीस हजार मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु निम्न शर्तों के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

2- स्वीकृत धनराशि का आहरण प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के हस्ताक्षर जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर युक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके इसी वित्तीय वर्ष में आहरित की जायेगी। आहरण से सम्बन्धित बिल बाउचर संख्या एवं दिनांक की सूचना शासन एवं महालेखाकार को आहरण के तुरन्त बाद उपलब्ध करायी जायेगी तथा यथा समय बी0एम0-08 व बी0एम0-13 पर विवरण भी शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय आवंटन के अनुसार ही किया जायेगा और किसी अन्य अनावुमोदित योजना पर व्यवर्तन अपने स्तर से नहीं किया जायेगा।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2008 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोग प्रमाण-पत्र (Utilization Certificate) शासन को प्रस्तुत किया जाय। उक्त विवरण प्रस्तुत करने के बाद ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी।

5- व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैंडबुक नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत शासकीय अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हों, उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। निर्माण कार्यों पर व्यय करने से पूर्व आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की टैक्निकल स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

१९

6. योजनाओं/कार्यों पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत आंगणन नार्म है। स्वीकृत आंगणन से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
7. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 8- सम्बन्धित योजनाओं/कार्यों हेतु यथावश्यकता सक्षम स्तर नियमानुसार प्राविधिक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
- 9- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग/विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
- 10- आगणन में जिन मदों हेतु जो धनराशि स्वीकृत की गई है उसी मद पर व्यय किया जाय एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
- 11- निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का सक्षम प्रयोगशाला में टैस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पाई जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय। कार्य उपरान्त भी किये गये कार्य की गुणवत्ता का तृतीय परन्तु सक्षम पक्ष से सत्यापन कराकर सम्बन्धित रिपोर्ट शासन को तत्काल प्रस्तुत की जाय।
- 12- समय-समय पर निर्गत वित्तीय नियमों व मितव्ययता सम्बंधी निर्देशों की अनुपावना की जाय।
- 13- कराये जाने वाले कार्यों पर वित्त लेखा अनुभाग-2 के शासनादेश सं०-ए-2-87(1)/दर-97-17(4)/275 दिनांक 27.02.97 के अनुसार सैंटेज व्यय किया जायेगा तथा कार्यों की कुल लागत के सापेक्ष पूर्व में व्यय की गयी धनराशि में सैंटेज के रूप में व्यय की गयी धनराशि को समायोजित करते हुए कुल सैंटेज वार्जेज 12.5 प्रतिशत से अधिक अनुमन्य नहीं होगा। इसे कृपया कड़ाई से सुनिश्चित कर लिया जाय।
- 14 आगणन में उल्लिखित दरें केवल आगणन गठित किये लिये ही अनुमन्य है। कार्य कराने से पूर्व दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को तथा जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन कराना आवश्यक होगा।
- 15 एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त कार्य टेकअप किया जाय।
- 16 निर्माण सामग्री क्रय करने से पूर्व स्टोर परचेज नियमों का कड़ाई से पालन किया जाय।
- 17 कार्य कराने से पूर्व स्थल का भलिभाँति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भू-गर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।
- 18 जी०पी०डब्लू० फार्म-9 की शर्तों के अनुसार निर्माण इकाईयों को कार्य सम्पादित कराना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।
- 19 मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य करते समय/कार्य करते समय कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

20- योजना पर 40 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त की जा रही है। अतः योजना का निर्माण सम्यबद्ध ढंग से पूर्ण किया जाना होगा। जिसके लिए योजना का पुनरीक्षित प्राक्कलन किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं होगा।

21- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 में अनुदान सं०-13 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2215-जलापूर्ति तथा सफाई-01-जलापूर्ति- आयोजनागत -102- ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम-03-ग्रामीण पेयजल राज्य सैक्टर - 00 -20- सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नामे" डाला जायेगा।

22- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं०- 465/xxvii(2)/2007 दिनांक 11 अक्टूबर, 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव

पृ० सं० १५६७/उन्तीस(2)/०६-2(173पे०)/200६ तददिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. मण्डलायुक्त कुमौयू/गढ़वाल मण्डल।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5. महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान गढ़वाल/कुमौयू।
6. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम गढ़वाल/कुमौयू।
7. वित्त अनुभाग-2/वित्त(बजट सैल)/राज्य योजना आयोग उत्तराखण्ड।
8. निजी सचिव, मा० पेयजल मंत्री को मा० मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
9. स्टाफ ऑफिसर-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
10. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
- ✓ 11. निदेशक, एन०आई०सी० सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(नवीन सिंह तड़ागी)

उप सचिव

